समिति का केन्द्रीय सड़क निधि संबंधी प्रतिवेदन

*260. **श्री महेश्वर सिंह :**
श्री मोहम्मद सलीम :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 23 फरवरी, 1994 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 24 और उसके पूरक प्रश्नों के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** समिति ने केन्द्रीय सड़क निधि के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके **कब** तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री **(श्री जगदीश** टाईटलर) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य, केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि के **बारे** में मंत्रियों के दल द्वारा लिए गए **निर्णय** के बारे में जानना **चाहतेहैं**। इस **मामले में अभी** तक अंतिम निर्णय **नहीं लिया गया है**। चूंकि, यह मामला **अभी भी सरकार के** विचाराधीन है, अत: **अभी से यह बता** पाना कठिन है निर्णय कब तक ल लिया जाएगा।

Toimentation ami 'Tearing ol Zoo Aal-mata by Visitors

2055. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether if is a fact that animals in various Zoos of the country are being tormented and teased by the visitors;

(b) whether it is also a fact tliat ibere hi *no* check on the visitors to deswt them #os thi* practice:

(c) whether it is also a fact that some instances of Sormentation and teasing have been, found to be in violation of the provisions of Prtvention of Cruelty to Animals Act; and

(d) if so, what deterrent steps Govern-mem propose to take to eradicate this tendency of the visitors at Zoo?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (d) It is true that some persons, who are not adequately sensitised towards the thics of wildlife man-agement, do indulge in teasing sometimes Teasing of animals in the Zoos in India is prohibited and the Zoo Authorities endeavour to prevent visitors from' doing it. However, sometimes, in order to see the animals in active state, some visitors, are reported to have indulge in teasing of zoo anmials, specially on busy days. Some of these instances could be found to be in violation of the provisions of the Prevention ot Cruelty to Animals Act. However, the act of teasing of animals in the zoos is now a violation of Section 38 J of tne Wildlife Protection Act, 1972, also, which provides for stringent plnishment to the offender. It is to be appreciated that these instances take place due to ignorance or lack of understanding about ani-m-il life nad welfare by the common people. Steps have been taken to strengthen the education and awareness programme in the major zoos to ensure self control by the visitors themselves.

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय और विदेशी सहायता से आरम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

2056. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में पर्यावरण में सुधार और वनों तथा वन्य-जीवों के विकास हेतु आरम्भ की गई केन्द्रीय तथा विदेशी-सहाय प्राप्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में अब तक की क्या उपलब्धि रही है ;

(ग) राज्य को इस प्रयोजन हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(घ) निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने बहुमूल्य वन्य-जीवों के संरक्षण और उनके विकास हेतु कोई विशेष योजना बनाई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय और विदेशी सहायता से पर्यावरण के सुधार और वनों और वन्यजीवों के विकास के लिए मध्य प्रदेश में शुरू की गई परियोजनाओं तथा इस प्रयोजन के लिए राज्य को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि के ब्यौरे अनुलग्नक के रूप में संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिये)**

(ख) सभी परियोजनाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

(घ) परियोजनाएं अनवरत स्वरूप की हैं।

(ङ) अनुलग्नक के विवरण में क्र० सं० 1–5 पर दर्शाई गई वन्यजीव संरक्षण की सभी वर्तमान स्कीमें जारी रहेंगी।

विवरण

वन्य जीवों के संरक्षण और उनके विकास हेतु विशेष योजनायें

क्र०सं०	स्कीम/परियोजना का नाम	मुख्य उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा निधियन की मात्रा	स्थिति	पिछले तीन वर्षों, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान बंटित राशि (रु० लाखों में)
केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीमें					
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	वित्तीय सहायता के जरिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास में राज्य को सहायता देना	100%	जारी	345.54

क्र० सं०	स्कीम/परियोजना का नाम	मुख्य उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा निधियन की मात्रा	स्थिति	पिछले तीन वर्षों, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान बंटित राशि (रु० लाखों में)
1	2	3	4	5	6
2.	हाथी परियोजना	हाथियों की दीर्घकालिक उत्तरजीवितता सुनिश्चित करना	100% अना० वर्ती 50% आवर्ती	जारी	17.92
3.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना	100% अना० 50% आ०	जारी	57.86
4.	बाघ परियोजना	बाघों की जीवनक्षम आबादी का अनुरक्षण सुनिश्चित करना	100% अना० 50% आ०	जारी	272.69
5.	बाघ परियोजना क्षेत्रों राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आदिवासी गांवों के लिए लाभभोगी उन्मुख स्कीम	पुनर्वास योजना के तहत आदिवासियों तथा अन्य परिवारों का पुनर्वास करना	100%	जारी	19.43
6.	समेकित वनीकरण एवं पारि-विकास स्कीम	वनीकरण और पारि-विकास को बढ़ावा देना	100%	जारी	1323.13
7.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकड़ी एवं चारा परियोजना स्कीम	ईंधन की लकड़ी की कमी वाले अभिनिर्धारित क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी एवं चारे की आपूर्ति बढ़ाना	50%	जारी	690.00
8.	बीज विकास स्कीम	अच्छे किस्म के बीजों के लिए अवसंरचना का विकास	100%	जारी	11.86

1	2	3	4	5	6
9.	हवाई बीजरोपण	कठिन एवं अगम्य क्षेत्रों में पुनः वनस्पति उगाना	100%	जारी	31.15
10.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पादों की खेती करना	100%	जारी	129.83
11.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	जनता की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना	100%	जारी	4.99
12.	अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना	जैवमास संसाधन आधार में सुधार करने के लिए अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना	100%	जारी	31.69
13.	मोटा नमभूमि का संरक्षण और प्रबंधन	नमभूमियों के संरक्षण के लिए उचित नीतियां अपनाना	100%	जारी	198.19
विदेशी सहायता प्राप्त नई परियोजनायें					
14.	विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	4 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्रदान की गई। परियोजना 1995–2001 के दौरान कार्यान्वित की जाएगी।		
15.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का सुदृढ़ीकरण— जर्मनी की सहायता प्राप्त परियोजना	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए उपकरण, प्रशिक्षण और सिविल निर्माण की व्यवस्था करना।	यह परियोजना अक्तूबर, 1994 से शुरू होगी।		

आ० – आवर्ती
अना० – अनावर्ती